1990—98, including Rs. 146.97 crore for elections related SRE. During the current year (1998-99), Central Government has advanced Rs. 20.00 crore as Special SRE under Action Plan for tackling miltancy in J&K. In addition Rs. 75.00 crore has also been released as advance for meeting SRE during the year. An SRE Parameters Review Committee with representatives of State and Central Government has recently reviewed the items which are admissible for reimbursement under SRE and have recommended that future releases be made accordingly.

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर दिल्ली पुलिस और सीमा शुल्क कर्मियों द्वारा आतंक फैलाया जाना

1912. श्री ईशदत्त यादव :
प्रो० रामगोपाल यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के "दैनिक जागरण' में "हवाई अड्डा माफिया–1" शीषक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर तैनात दिल्ली पुलिस व कस्टम विभाग के कर्मियों के गैगों का आतंक से यात्रियों को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी इक्का-दुक्का घटनाएं घटी हैं जिनमें यात्रियों ने शिकायत की है कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने उनसे धन ऐंठा है, लेकिन इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है कि हवाई अड्डे पर ऐसा कोई "गिरोह" सक्रिय है ।

जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तभी व्यक्तिगत मामलों में उचित कानूनी/विभागीय कारवाई की जाती है ।

(ग) इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त द्वारा रात्रि के समय आकस्मक निरीक्ष किये जाते हैं जिसके दौरान यात्रियों को उनके सामने पेश आ रही कठिनाईयों को निसंकोच व्यक्त करन के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । लोक शिकायतों को सुनने के लिये हवाई अड्डे पर चौबीसों घंटे सीमा शुल्क विभाग का सहायक आयुक्त स्तर का एक अधिकारी भी तैनात रहता है । इसके अलावा, जब कभी परेशान किये जाने के ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिलती है ध्यान में लाया जाता है तो समुचित विभागीय कारवाई शुरू की जाती है ।

Scrapping of Official Secrets Act

1913. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI K. M. KHAN:
SHRI AMAR SINGH:
SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI JANESHWAR MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to scrap the Official Secrets Act in near future;

(b) if so, the details thereof with circumstances prompted for such move;

(c) whether such move is to ensure transparency and freedom of information in the country;

(d) whether such transparency wili include declaration of sensitive defence installations and development in the country;

(e) whether the transparency will also include openness of Government towards all sensitive schemes and programmes;

(f) if not, the areas to be affected by scrapping of the Official Secrets Act?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (f) No, Sir.

However, the issue relating to amendments to the Official Secrets Act, 1923, is clubbed with the formulation of Freedom of Information Bill which is under examination of the Government.

per inmate food authorisation in jails

1914. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN:

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the per inmate food authorised in various jails in the country;

(b) whether the food available for the inmates in jails fulfil the required calories for subsistence level;

(c) if so, the item-wise food provided and the calories generated; and

(d) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (d) 'Prisons' is a State subject as per Entry 4 of the State List of the Seventh Schedule of the Constitution of India. It is essentially for the State Governments to prescribe such diet scales for prisoners as are necessary as per local requirements and food habits, etc., information about diet scales provided by different States is not maintained centrally.

Presidential form of Government

1915. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Commission to study the question of introducing Presidential form of Government in the country;

(b) whether all the formalities in this regard have been completed; and

(c) if so, what is the present status of the proposal?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c) The Government has no such proposal. However, the Government does propose to review the Constitution of India in the light of the experience of the past fifty years and to make suitable recommendations, without altering the basic structure of the Constitution.

कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड

1916. **श्री अन्नतराय देवशंकर दवे:**

क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को संविधान में संशोधन करके कच्छ क्षेत्र हेतु एक पृथक विकास बोर्ड गठित करने के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात विधान सभा ने इस संबंध में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है ; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में मंजूरी देने का विचार रखती है ?